केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की मांगें

1753. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की कौन-कौन सी मांगें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) मांग की प्रत्येक मद पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है तथा लिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा पेंशन संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श किए जाने की प्रक्रिया के दौरान, पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगें उपर्युक्त आयोग को प्रस्तुत की थीं। आयोग ने कुछ प्रतिनिधि संगठनों की मांगें सुनी भी थीं। इन मांगों के साथ-साथ, संपूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात्, उपर्युक्त वेतन-आयोग ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में पेंशन और पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के बारे में सिफारिशें कीं। पेंशन और उससे संबद्ध मामलों से संबंधित सभी 38 सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच-पड़ताल की गई, उन पर निर्णय लिए गए और निम्नलिखित से संबंधित, मुद्दों को छोड़कर, जहां कहीं आवश्यक था, आदेश जारी किए गए:

(i) पेंशन-निधि की स्थापना;

(ii) 33 वर्ष से परे, की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के संबंध में पेंशन में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी; और

(iii) पेंशन का परिकलन, इस समय अंतिम 10 माह की अवधि की औसत परिलब्धियों के आधार पर किए जाने के स्थान पर अंतिम 6 माह की अवधि की परिलब्धियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

Implementing the recommendations of Fifth Pay Commission

1754. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Joint Platform of Action (JPA) has demanded an immediate halt to the implementation of the controversial reform related recommendations of the fifth pay Commission, such as abolition of about 3.5 lakh sanctioned vacant posts, reduction in existing workforce of Government, resulting in abolition of another 12 lakh posts, etc; and

(b) if so, Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) No general decision has been taken on the recommendation of the Fifth Central Pay Commission for abolishing posts under the Government. Matters relating to abolition or creation of posts are decided on the basis of merits and need.

Arrest of Government officials on corruption charges

1755. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details of senior Government officials arrested on charges of corruption in the recent period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, as the Cadre Controlling Authority in respect of the officers belonging to the Indian Administrative Service, has placed three IAS officers (of and above the rank of Deputy Secretary) under suspension on corruption charges in the recent period. The above mentioned three officers were working in the affairs of the Union Government at the time of their suspension.